कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष:64 अंक:7 मुम्बई जून 2020

खादी और ग्रामोद्योग आयोग - स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आगे आया

स्थानीय से वैश्विक

खादी मास्क की विदेशी बाजारों में दस्तक

GO SWADESHI WITH KHADI MASKS

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष:64 अंक:7 मुम्बई जून 2020

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

उप संपादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी
सरस्वती खनका

डिजाईन व पृष्ठसज्जा
सुबोध कुमार

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056
के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में

समाचार सार ..... 3 से 17

खादी और ग्रामोद्योग आयोग - स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आगे आया....

श्री अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला.....

गृह मंत्री श्री अमित शाह का स्वदेशी पर व्यापक जोर: केवीआईसी भारत भर में अर्धसैनिक बलों के कैंटीन में स्थानीय उत्पाद उपलब्ध कराएगा.....

स्थानीय से वैश्विक-आत्मनिर्भर भारत:खादी मास्क की विदेशी बाजारों में दस्तक.....

कंपनियां "खादी" ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके नकली पीपीई किट बेच रही हैं, केवीआईसी कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है.....

500 करोड़ रुपये की सहायता से भारत में मधुमक्खी पालन उद्योग में मधु क्रांति आएगी: केवीआईसी.....

2019-20 में खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार लगभग 90,000 करोड़ रुपये पहुंचा.....

बाड़मेर के कुम्भकारों ने मटकों के जरिये कोरोना के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया.....

पीएमईजीपी योजना की बाधाओं को दूर करने की कवायद शुरु खादी और ग्रामोद्योग आयोग सुनिश्चित करेगा तीव्र निष्पादन.....

सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियन्स पोर्टल शुरु किया.....

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर .....18 से 20

खादी और ग्रामोद्योग आयोग - स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आगे आया

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर' बनने और इसे "वैश्विक" बनाने के लिए किए गए आह्वान के प्रति कमर कस लिया है। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील के एक दिन बाद, केवीआईसी ने प्रमुख कार्यक्रम पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए दिशा-निर्देशों को जारी किया है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने आज संबंधित एजेंसियों को पीएमईजीपी के अंतर्गत आने वाले आवेदनों की जांच करने और 26 दिनों के अंदर धन का वितरण करने के लिए उन्हें बैंकों को भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसकी समय-सीमा को घटाकर 15 दिन करने का भी निर्देश दिया है। एजेंसियों के लिए, प्रस्ताव तैयार करने में आवेदकों का मार्गदर्शन करना और ऋण की स्वीकृति होने तक उनकी सहायता करना अनिवार्य होगा। सभी एजेंसियां ऋण की जल्द से जल्द मंजूरी प्राप्ति के लिए बैंकों के साथ आगे की कार्यवाही करेंगी।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुंबई में केवीआईसी का मॉनिटरिंग सेल दैनिक आधार पर आवेदन के प्रक्रिया की निगरानी करेगा जबकि वह प्रत्येक पखवाड़े में क्रियान्वयन एजेंसियों को फीडबैक प्रदान करेगा। इसके बाद, प्रगति रिपोर्ट को केवीआईसी के सीईओ और चेयरमैन के सामने अवलोकन के लिए रखा जाएगा।

श्री सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्थानीय उत्पादनों को प्रोत्साहित करने की अपील के मद्देनजर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, "जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, 'आत्म-निर्भरता' ही मंत्र है। पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने से स्थानीय विनिर्माण के विकास में और तेजी आएगी। इसके माध्यम से कम से कम समय-सीमा के अंदर, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन सुनिश्चित किया जा सकेगा।" श्री सक्सेना ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग का स्थानीय रूप से वैश्विक रूप में परिवर्तन, अन्य स्थानीय उद्योगों और उद्यमों के लिए एक गहन अध्यन का विषय होगा। उन्होंने कहा कि, "केवीआईसी एक नोडल एजेंसी के रूप में, पीएमईजीपी के अंतर्गत आने वाली आगामी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।"

स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय

श्री अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला

श्री अरविंद कुमार शर्मा (आईएएस) ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। युद्धस्तर पर काम की शुरुआत करते हुए, उन्होंने मंत्रालय के कामों की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की और आवश्यक मुद्दों विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा की।

श्री शर्मा ने इस बात पर बल दिया है कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तात्कालिक परिस्थिति से निपटने के पश्चात, हमें एमएसएमई में से वैश्विक चैंपियन कंपनियों का निर्माण करने की दिशा में काम करने की जरूरत है।

इस नियुक्ति से पहले, श्री शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे थे। वे गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

श्री शर्मा ने गुजरात सरकार में फील्ड और पॉलिसी स्तर सहित विभिन्न पदों पर भी काम किया है और उन्हें नियामक और विकासात्मक प्रशासन, आपदा प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रबंधन, औद्योगिक/निवेश संवर्धन और अवसंरचना विकास विभागों को संभालने का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

लिया गया है कि प्रत्येक जिले में एन95 मास्क, वेंटिलेटर या उनका सामान, चिकित्सा कर्मचारियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर/ लिक्विड हैंड वॉश, थर्मल स्कैनर और अगरबत्ती और साबुन के निर्माण से संबंधित कम से एक इकाई स्थापित की जाएगी। यह देश में मौजूदा कोविड-19 के संकट के कारण बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए है।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, जांच के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक ने 100 अंकों की तालिका में कम से कम 60 अंक प्राप्त किया है। इसी प्रकार, कच्चे माल की उपलब्धता, जनशक्ति, परिवहन और बिजली तक पहुंच जैसी तकनीकी व्यवहार्यता की भी जांच की जानी चाहिए, जिससे कि बैंक के स्तर पर अस्वीकृति को कम किया जा सके।

इसी प्रकार, कार्यान्वयन एजेंसियों को बाजार का अध्ययन, प्रस्तावित उत्पाद की मांग का आंकलन, आसपास के इलाकों में इसी प्रकार के उत्पादों से संबंधित परियोजनाएं और बाजार की रणनीति की भी जांच करनी होगी। एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि यह प्रस्ताव चयनित बैंक के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे कि क्षेत्राधिकार को आधार बनाकर इसकी अस्वीकृति नहीं की जा सके।

गृह मंत्री श्री अमित शाह का स्वदेशी पर व्यापक जोर: केवीआईसी भारत भर में अर्धसैनिक बलों के कैंटीन में स्थानीय उत्पाद उपलब्ध कराएगा

भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के आह्वान के तुरंत बाद, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक मोर्चा संभाला है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से अर्धसैनिक बलों के सभी कैंटीनों और दुकानों पर केवल स्वदेशी उत्पादों को बेचने के लिए अनिवार्य कर दिया है। इस कदम से किसानों, बेरोजगार युवाओं और कुटीर और ग्रामोद्योग से जुड़े लाखों लोगों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे।

इस आशय का एक आदेश 15 मई 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है जो 1 जून, 2020 से लागू हुआ है । अब केवल भारतीय उत्पाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कैंटीन के माध्यम से बेचे जाएंगे, जो केवीआईसी द्वारा खरीदे जाएंगे । यह निर्णय केवीआईसी के उत्पादन और बिक्री को भी प्रोत्साहित करेगा जो इन दुकानों पर आपूर्ति के बहुमत को पूरा करेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 17 उत्पादों को केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) के साथ पंजीकृत किया गया है। अब गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल स्वदेशी उत्पादों को केपीकेबी भंडारों के माध्यम से 1 जून, 2020 से बेचा जाएगा। उपरोक्त के मद्देनजर, सभी मास्टर भंडार अपनी मांगों को सीधे केवीआईसी में रख सकते हैं।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्री श्री अमित शाह के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे एमएसएमई इकाइयों के अलावा कुटीर और ग्रामोद्योग क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। "इस फैसले से विभिन्न ग्रामोद्योग उत्पादों के विनिर्माण से जुड़े लाखों लोगों को सीधे लाभ होगा। इस आदेश के साथ विभिन्न अर्धसैनिक बलों के 10 लाख से अधिक कर्मियों को केवीआईसी के उपभोक्ता आधार में जोड़ा जाएगा। श्री सक्सेना ने कहा कि इसे सद्भावना के संकेत के रूप में, केवीआईसी ने भी तुरंत सीएफएफ कैंटीन को 3% के छोटे अंतर पर उत्पादों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है, जबकि अन्य मामलों में यह 20% मार्जिन है।

विशेष रूप से, देश भर में इन अर्ध सैनिका बलों के 20 मास्टर भंडार हैं, जिनका वार्षिक कारोबार 1800 करोड़ रुपये से अधिक है। केवीआईसी को कुल कारोबार का बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना है। वर्तमान में, केवीआईसी ने सीएपीएफ कैंटीन को आपूर्ति के लिए 17 उत्पादों को पंजीकृत किया है।

इनमें खादी राष्ट्रीय ध्वज, शहद, अचार, खाद्य तेल, अगरबत्ती, पापड़, आंवला उत्पाद और सूती खादी के तौलिये आदि जैसी अन्य वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा खादी के कपड़े, ऊनी कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन जैसे हर्बल तेल, शैम्पू, साबुन, फेस वाश, चाय और कॉफी और अन्य जैसे 63 नए उत्पादों को इन दुकानों पर आपूर्ति सूची में शामिल करने के लिए केवीआईसी द्वारा सीएपीएफ कैंटीन को प्रस्तुत किया गया है।

स्थानीय से वैश्विक...
आत्मनिर्भर भारत
खादी मास्क की विदेशी बाजारों में दस्तक

व्यापक रूप से लोकप्रिय खादी फेस मास्क "वैश्विक" होने के लिए तैयार है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के गैर-चिकित्सा/ गैर-सर्जिकल मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिए जाने के बाद, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अब विदेशों में खादी कॉटन और रेशम फेस मास्क के निर्यात की संभावनाओं का पता लगा रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से इस संदर्भ में 16 मई को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

यह कदम, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "आत्मनिर्भर भारत अभियान" को ध्यान में रखते हुए "स्थानीय से वैश्विक" आह्वान के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान फेस मास्क की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए, केवीआईसी ने क्रमशः दो स्तरीय और तीन स्तरीय कॉटन के साथ-साथ सिल्क फेस मास्क को विकसित किया है, जो पुरुषों के लिए दो रंगों में और महिलाओं के लिए कई रंगों में उपलब्ध हैं।

अब तक केवीआईसी को 8 लाख फेस मास्क की आपूर्ति के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं और लॉकडाउन अवधि के दौरान 6 लाख से ज्यादा फेस मास्क की आपूर्ति की जा चुकी है। केवीआईसी को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, जम्मू-कश्मीर सरकार से ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और आम नागरिकों द्वारा ईमेल के माध्यम से ऑर्डर मिले हैं। फेस मास्क की बिक्री करने के अलावा, पूरे देश में खादी संस्थाओं द्वारा जिला प्राधिकरणों को 7.5 लाख से अधिक खादी फेस मास्क मुफ्त में बांटे गए हैं।

केवीआईसी की योजना दुबई, अमेरिका, मॉरीशस और

मास्क के निर्यात से उत्पादन में गतिशीलता आएगी और अंततः भारत में कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। श्री सक्सेना ने यह भी कहा कि "फेस मास्क कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। खादी फैब्रिक से तैयार ये डबल ट्विस्टेड मास्क न केवल गुणवत्ता और मांग के पैमाने पर खरे उतरते हैं बल्कि वे लागत प्रभावी, सांस लेने में उपयुक्त, धोने योग्य, पुन: उपयोग करने योग्य और बायो-डिग्रेडेबल हैं।"

कई यूरोपीय और मध्य पूर्व देशों में खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की है, जहां पर पिछले कुछ वर्षों में खादी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। केवीआईसी की योजना इन देशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से खादी फेस मास्क बिक्री करने की है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी फेस मास्क का निर्यात, 'स्थानीय से वैश्विक' होने का सबसे बढ़िया उदाहरण है। श्री सक्सेना ने कहा, "प्रधानमंत्री की अपील के बाद हाल के वर्षों में खादी के कपड़े और अन्य उत्पादों की लोकप्रियता पूरी दुनिया में काफी बढ़ी है। खादी फेस

इन मास्क के निर्माण में केवीआईसी द्वारा विशेष रूप से डबल ट्विस्टेड खादी कपड़े का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह नमी की मात्रा को अंदर तक बनाए रखने में मददगार साबित होता है और हवा को अंदर जाने देने के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है। इन मास्क को जो बात विशेष रूप से खास बनाती है वह हाथ से बुने हुए कॉटन और सिल्क के कपड़े हैं। कॉटन एक मैकेनिकल अवरोधक के रूप में जबकि रेशम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अवरोधक के रूप में काम करता है।

कंपनियां "खादी" ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके नकली पीपीई किट बेच रही हैं, केवीआईसी कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के संज्ञान में यह आया है कि कुछ बेईमान व्यावसायिक कंपनियां व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट का निर्माण और बिक्री कर रही हैं और धोखे से केवीआईसी के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'खादी इंडिया' का उपयोग कर रही हैं। केवीआईसी ये बात स्पष्ट करता है कि अब तक उसने कोई पीपीई किट बाजार में नहीं उतारी है।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि ये नकली पीपीई किट खादी के ही एक उत्पाद की तरह बेची जा रही है, जो पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि केवीआईसी विशेष रूप से अपने उत्पादों के लिए डबल ट्विस्टेड वाले हाथ से काते हुए, हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े का उपयोग करता है और इसलिए पॉलिएस्टर और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे बिना बुने हुए मटीरियल से बने ये किट न तो खादी के उत्पाद हैं और न ही केवीआईसी उत्पाद हैं।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि केवीआईसी ने खादी कपड़े से बने अपने स्वयं के पीपीई किट विकसित किए हैं जो परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर हैं। उन्होंने कहा, "अभी तक हमने खादी पीपीई किट बाजार में नहीं उतारी हैं। पीपीई किटों को 'खादी इंडिया' के नाम पर धोखेबाज़ी से बेचना गैर-कानूनी है। इसके अलावा ये किट हमारे डॉक्टरों, नैदानिक चिकित्सा सहायकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं जो कोरोना बीमारी के मामलों से नियमित रूप से लड़ रहे हैं।" श्री सक्सेना ने कहा कि केवीआईसी ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।

दिल्ली स्थित एक 'निचिया कॉर्पोरेशन' द्वारा बनाई गई नकली पीपीई किट का मामला केवीआईसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य नारायण के ध्यान में लाया गया, जिन्होंने बताया कि केवीआईसी ने कोई भी पीपीई किट लॉन्च नहीं किया है और न ही इसका काम किसी निजी एजेंसी को दिया है।

वर्तमान में, केवीआईसी केवल विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए खादी फेस मास्क का निर्माण और वितरण कर रहा है जो उच्चतम सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। केवीआईसी इन मास्क के निर्माण के लिए डबल-ट्विस्ट वाले खादी कपड़े का उपयोग कर रहा है क्योंकि यह 70 फीसदी नमी को अंदर ही बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये मास्क हाथ से काते और हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े से बने होते हैं जो सांस लेने, धोने योग्य और बायोडिग्रेडेबल होते हैं।

500 करोड़ रुपये की सहायता से भारत में मधुमक्खी पालन उद्योग में मधु क्रांति आएगी: केवीआईसी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), प्रत्येक वर्ष 20 मई को "विश्व मधुमक्खी दिवस" मनाता रहा है, मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास के लिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को घोषित 500 करोड़ रुपये का पैकेज जो भारत के किसानों, आदिवासी और बेरोजगार युवाओं के लिए एक पूर्ण राहत पैकेज है। किसानों और मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य के साथ घोषित 500 करोड़ रुपये का पैकेज, शहद उत्पादन में वृद्धि, क्रॉस परागण के माध्यम से 35 प्रतिशत से अधिक भारत की कृषि उपज बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने जैसे कई मध्यवर्ती लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और जिसका अंतिम लक्ष्य भारत में "मीठी क्रांति" के सपने को साकार करना है।

मई 2019 में एमएसएमई मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, माननीय श्री नितिन गडकरी ने "स्वीट क्रान्ति" के स्वप्न को साकार करने की इच्छा व्यक्त की थी। मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता का श्रेय श्री गडकरी को जाता है।

वित्तीय वृद्धि के साथ, भारत जल्द ही दुनिया के शीर्ष तीन शहद उत्पादक देशों में शामिल हो जाएगा। वर्तमान में, भारत शहद उत्पादक देशों के मामले में आठवें स्थान पर है, चीन दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि 'हनी मिशन' का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "देश में मीठी क्रांति" के आह्वान को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन उद्योग की वृद्धि से देश में कृषि उपज बढ़ेगी और अंततः किसानों और मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि होगी। तीन साल से भी कम समय में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की लंबाई और चौड़ाई में 1.33 लाख मधुमक्खी के बक्सों का- उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र के पश्चिमी तट से लेकर पूर्व में सुंदरवन तक - वितरण किया है।

श्री सक्सेना ने कहा, "मधुमक्खी पालन उद्योग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से अकेले 5 को कवर करता है, यानी आजीविका उत्पादन, भूख के खिलाफ लड़ाई, जैव विविधता को बढ़ावा देना, भूखमरी को दूर करना और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना। इसके अलावा, शहद का सेवन बढ़ाने से स्वास्थ्य लाभ भी होगा क्योंकि यह प्रतिरक्षा को बढ़ाता है।" श्री सक्सेना ने आगे कहा, "किसानों, आदिवासियों, मधुमक्खी पालकों को सीधे लाभ के अलावा, यह विशेष आवंटन देश में स्वीट क्रांति के लिए एकदम सही लॉन्च पैड बन जाएगा क्योंकि मधुमक्खी पालन से मधुमक्खियों के बक्सों, मधुमक्खी के

छत्ते के निर्माण व उपकरण, मधुमक्खी कॉलोनियों और शहद प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना संबंधित आदि जैसे कई कार्यों के अवसर खुलेंगे।"

वर्तमान में, भारत में शहद की खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 5 ग्राम से कम है, जबकि यह दुनिया के अन्य देशों में 1 किलोग्राम - 2 किलोग्राम के बीच है।

केवीआईसी द्वारा हनी मिशन को 2017-18 में 10 करोड़ रुपये के छोटे बजट के साथ शुरू किया गया था, और केवीआईसी को 2018-19 में एमएसएमई मंत्रालय से 49 करोड़ रुपये का आवंटन मिला। तीन वर्षों से भी कम समय में, 13,466 मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया गया है और एक 1.33 लाख मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए हैं और वे सक्रिय रूप से हनी उत्पादन में लगे हुए हैं।

जून 2018 में, केवीआईसी ने एक ही दिन में मधुमक्खी-बक्से के वितरण की अधिकतम संख्या यानी 2330 मधुमक्खी बक्से के वितरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह मई 2018 में काजीरंगा वन क्षेत्र, असम की मूसिंग जनजाति को अपने पिछले 1000 सर्वश्रेष्ठ बक्सों वितरित के रिकार्ड को पछाड़ कर कश्मीर के कुपवाड़ा में 2330 मधुमक्खी बक्से के वितरित कर केवीआईसी द्वारा नया मुकाम हासिल किया गया। मधुमक्खी पालन के बड़े पर्यावरणीय लाभ भी हैं, क्योंकि कम से कम 35% वैश्विक कृषि भूमि, परागण से प्रभावित होती है।

हाल के वर्षों में, भारत का शहद उत्पादन बढ़ा है। भारत ने वर्ष 2018-19 के दौरान 732.1 करोड़ रुपये मूल्य के 61,333 मीट्रिक टन प्राकृतिक हनी का निर्यात किया। यूएसए, यूएई, सऊदी अरब, मोरक्को और कतर भारत के हनी के प्रमुख आयातक रहे हैं।

2019-20 में खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार लगभग 90,000 करोड़ रुपये पहुंचा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में, भारत में 'ब्रांड खादी' की स्वीकार्यता व्यापक रूप से देखने को मिली है। जबकि दीर्घकालिक विकास के लिए सबसे अनुकूल पर्यावरण उत्पाद खादी का उत्पादन, पिछले पांच वर्षों में दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है, यानी 2015–16 के बाद से; इसी अवधि के दौरान खादी की बिक्री में लगभग तीन गुनी बढ़ोत्तरी देखी गई है।

इसी प्रकार, ग्रामोद्योग (वीआई) क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में भी पिछले पांच वर्षों में लगभग 100% की अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी देखी गई है।

पिछले एक वर्ष में खादी के कारोबार के प्रदर्शन का अवलोकन करते हुए, यह 2018-19 में 3215.13 करोड़ रुपये था, जिसमें 31% की वृद्धि दर्ज करते हुए, यह 2019-20 में 4211.26 करोड़ रुपये हो गया। ग्रामोद्योग उत्पादों का कारोबार 2019-20 में 84,675.39 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 19% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 2018-19 में 71,077 करोड़ रुपये था।

वर्ष 2019-20 में, खादी एवं ग्रामोद्योग का कुल कारोबार 88,887 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी के अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सतत प्रयासों, एमएसएमई मंत्री, श्री नितिन गडकरी के रचनात्मक विपणन विचारों और विभिन्न मंत्रालयों के सक्रिय सहयोग को श्रेय दिया है।

श्री सक्सेना ने कहा, "खादी उद्योग को पुनर्जीवित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों और खादी को दैनिक जीवन की आवश्यकता के रूप में अपनाने के लिए, प्रधानमंत्री द्वारा अपने रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बार-बार अपील करने के परिणामस्वरूप, केवीआईसी विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है"।

आंकड़ों के अनुसार, 2015-16 में खादी का उत्पादन 1,066 करोड़ रुपये आंका गया था, जो कि वर्ष 2019-20 में बढ़कर 2,292.44 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 115% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, खादी की बिक्री और भी ज्यादा रही । खादी फैब्रिक उत्पादों की बिक्री 2015-16 में 1,510 करोड़ रुपये थी, जो कि 2019-20 में 179% बढ़कर 4,211.26 करोड़ रुपये हो गई।

2015-16 में ग्रामोद्योगों के उत्पादों का उत्पादन 33,425 करोड़ रुपये का किया गया था और यह उत्पादन 2019-20 में 96% की बढ़ोत्तरी के साथ 65,393.40 करोड़ रुपये हो गया । 2015-16 में ग्रामोद्योगों के उत्पादों की बिक्री 40,385 करोड़ रुपये थी, जिसमें लगभग 110% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2019-20 में 84,675.39 करोड़ रुपये हो गयी।

(शेष पृष्ठ 14 पर...)

बाड़मेर के कुम्भकारों ने मटकों के जरिये कोरोना के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के "कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम" से जुड़े

बारां जिले के किशनगंज उपखंड क्षेत्र के कुम्भकार परिवारों के बाद अब बाड़मेर जिले के विशाला गाँव के कुंभकार परिवारों ने भी अपने हुनर से कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया है। इन परिवारों द्वारा बनाये जाने वाले मटकों पर कोविड-19 से बचाव के संदेश को उकेरा गया है। मटकों पर "घर रहें सुरक्षित रहें", "कोरोना को हराना है बार-बार साबुन से हाथ धोना है", "मास्क का प्रयोग करें" जैसे संदेश लिखे गए है।

इन कुम्भकार परिवारों का मानना है कि व्यक्ति जितनी बार पानी पीएगा उतनी बार इन संदेशों को पढ़ेगा और कोरोना से सचेत रहेगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही मटकियों की बिक्री भी बढ़ेगी और उनका संदेश ज्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा।

पहले जनजाति बहुल बाराँ जिले और अब सीमावर्ती जिले बाड़मेर के कुम्भकार परिवारों की ओर से की गई यह पहल छोटी ही सही लेकिन असरदार और प्रशंसनीय है।

किशनगंज और विशाला के यह परिवार केंद्र सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजना "कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम" से जुड़े हैं। यह कार्यक्रम राजस्थान के 12 जिलों में चलाया जा रहा है जिनमें जयपुर, कोटा, बाराँ, झालावाड़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर प्रमुख है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुम्हार समुदाय के हुनर को बेहतर बनाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके लिए उन्हें मिट्टी को गूंधने के लिए मशीनें और मटके तथा अन्य उत्पाद बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चाक दिये गए है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय

कुमार सक्सेना ने राजस्थान के कुम्भकार परिवारों की ओर से कोरोनो को हराने के लिए की गई इस पहल की सराहना की है।

उन्होंने कहा कि जागरूकता फैलाने का यह अनोखा तरीका कई अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत बनेगा।

श्री सक्सेना ने बताया कि "कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम" से जुड़ने के बाद उनकी आय में सात से आठ गुना वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम से करीब 60 हजार परिवारों को फायदा हो रहा है।

गर्मी के मौसम में मटका लगभग हर घर की जरूरत है। मटकों पर माँड्णे और चित्रकारी करने की पुरानी परंपरा है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में मिट्टी के शिल्पकारों ने माँड्णे और चित्रकारी के बजाय मटकों पर कोरोना महामारी से बचाव के संदेश लिख लिखकर न सिर्फ अपनी समझदारी का परिचय दिया है बल्कि लोगों को इस गंभीर बीमारी से सतर्क करने की ज़िम्मेदारी उठाई है।

समाज के लोगों ने इससे पहले भी प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में दीपक जलाने के लिए लोगों को खादी ग्रामोद्योग आयोग के निर्देश पर निःशुल्क मिट्टी के दीयों का वितरण किया था। साथ ही पक्षियों के लिए परिंडे बनाकर उनका भी वितरण किया जा रहा है।

(पृष्ठ 12 से आगे.....)

2019-20 में खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार लगभग 90,000 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचा.....

खादी परिधानों के अलावा, ग्राम उद्योग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और शैंपू, आयुर्वेदिक दवाएं, शहद, तेल, चाय, अचार, पापड़, हैंड सैनिटाइजर, मिष्ठान्न, खाद्य पदार्थ और चमड़े की वस्तुओं ने भी बड़ी संख्या में देश-विदेश के उपभोक्ताओं को आकर्षित किया है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले पांच वर्षों में ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में लगभग दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है।

यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि केवीआईसी ने विभिन्न राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एयर इंडिया, आईओसी, ओएनजीसी, आरईसी और अन्य, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, भारतीय रेल और स्वास्थ्य मंत्रालय का समर्थन जुटाने में निरंतर रूप से प्रगति की है। इसके अलावा, ग्रामोद्योग क्षेत्र में, केवीआईसी मधुमक्खी पालन, मिट्टी के बर्तन और बेकरी जैसे 150 से ज्यादा क्षेत्रों में इन-हाउस क्षमता के साथ उत्कृष्ट उत्पादों का दावा करता है।

पीएमईजीपी योजना की बाधाओं को दूर करने की कवायद शुरु खादी और ग्रामोद्योग आयोग सुनिश्चित करेगा तीव्र निष्पादन

देश में रोजगार सृजन की गति तेज होने जा रही है। एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय में, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने इस बारे में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स कमेटी की भूमिका को खत्म करने का फैसला किया है ताकि समूची प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमईजीपी योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), उचित विचार विमर्श के बाद भावी उद्यमियों के प्रस्तावों / आवेदनों को सीधे मंजूरी दे देगा और आगे ऐसी योजनाओं के लिए ऋण उपलब्धता के बारे में फैसला लेने के लिए इन्हें बैंकों को भेज देगा । अब तक ऐसे प्रस्तावों को डीएलटीएफसी द्वारा छानबीन के बाद मंजूरी दी जाती थी जिससे अक्सर देरी होती थी।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने में डीएलटीएफसी को बंद करने के साथ एक बड़ी अड़चन को हटा दिया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी को देश हित में तेजी से कदम उठाने के लिए धन्यवाद दिया।

सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब कोरोना बीमारी के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन के कारण रोजगार क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नीतियों में यह बदलाव परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और पीएमईजीएस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

अक्सर ऐसा देखने में आता था कि डीएलटीएफसी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर / मजिस्ट्रेट ज्यादातर समय स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों में व्यस्त रहते थे जिसके कारण पीएमईजीपी से जुड़ी परियोजनाओं के अनुमोदन से संबंधित कार्य उनकी प्राथमिकता में नहीं रहते थे । ऐसे में योजना के प्रस्ताव कई महीनों तक लंबित रह जाते थे क्योंकि जिला कलेक्टर नियमित आधार पर मासिक बैठकें आयोजित करने में विफल रहते थे। इस बाधा को दूर करने के लिए, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने केंद्रीय मंत्री, श्री नितिन गडकरी को 20 अप्रैल को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया था।

श्री सक्सेना ने कहा "हम आभारी हैं कि माननीय मंत्री ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और डीएलटीएफसी की भूमिका खत्म करने का निर्णय लिया । इससे परियोजनाओं का त्वरित और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। सरकार का यह फैसला देश के लाखों लोगों के हित को सुरक्षित करेगा, जो पीएमईजीपी के तहत रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं।"

28 अप्रैल, 2020 को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि "सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि योजना के दिशानिर्देशों के खंड 11.9 के तहत गठित डीएलटीएफसी की भूमिका वित्तपोषण करने वाले बैंकों के लिए आवेदन प्रस्तावों की सिफारिश के बारे में बंद हो सकती है

मंत्रालय ने यह भी आदेश दिया है कि "वर्तमान में डीएलटीएफसी के स्तर पर लंबित सभी पीएमईजीपी के आवेदन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वापस लिए जा सकते हैं और ऋण उपलब्धता के बारे में निर्णय लेने के लिए बैंकों को तुरंत अग्रेषित किए जा सकते हैं।"

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदन प्राप्त करने के बाद केवीआईसी प्रस्तावों की जांच करेगा और सही आवेदनों को

क्रेडिट निर्णय लेने के लिए बैंकों को भेजा जाएगा। पीएमईजीपी योजना के तहत, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं। उद्योग, जिसमें क्षेत्र के आधार पर 15 से 35% सब्सिडी प्रदान की जाती है।

केवीआईसी, बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक स्कोरिंग शीट विकसित करेगा और पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर इसे अपलोड करेगा। स्कोरिंग शीट भी आवेदकों को अपने स्तर पर अपने आवेदनों को परखने और इस तरह से प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में सक्षम बनाएगी।

यहां यह उल्लेख करना जरुरी है कि केवीआईसी पूरे भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीएमईजीपी, भारत सरकार की प्रमुख रोजगार सृजन योजना, हर दिन एक नई सफलता की कहानी गढ़ रही है।

यह उल्लेखनीय है कि 2008 में शुरु होने के बाद से, पीएमईजीपी योजना प्रति वर्ष औसतन 35,000 आवेदन प्राप्त कर रही थी। हालांकि, 2016 में केवीआईसी ने उपयोगकर्ता के अनुकूल पीएमईजीपी पोर्टल विकसित किया और योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए जुलाई 2016 में इसे शुरु किया। ऑनलाइन सुविधा को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिली और ऑनलाइन आवेदनों की संख्या में प्रति वर्ष चार लाख तक की वृद्धि हुई, जो खुद इस योजना की लोकप्रियता को दर्शाता है।

आवेदनों की संख्या में वृद्धि के साथ, परियोजनाओं की संख्या में पिछले तीन वर्षों में केवीआईसी द्वारा वितरित परियोजनाओं की संख्या और सब्सिडी की मात्रा में भारी वृद्धि देखी गई है। पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं की संख्या 2016-17 में 52,912 से बढ़कर 2018-19 में 73,427 हो गई। इस अवधि के दौरान सब्सिडी की राशि भी 2016-17 में 1281 करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 2070 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 2017-18 में 48,398 परियोजनाओं की स्थापना की गई जबकि केवीआईसी ने इसके लिए 1312 करोड़ रुपये जारी किए। उत्पन्न कुल रोजगार भी 2016-17 में 4,07,840 व्यक्तियों से बढ़कर 2018-19 में 5,87,416 व्यक्ति हो गया है।

वर्ष 2019-20 में, केवीआईसी ने 1951 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी जारी की और देश में 66,653 परियोजनाओं की स्थापना की। केवीआईसी ने वर्ष 2019-20 में 2400 करोड़ रुपये के संवितरण पर 77,000 परियोजनाओं का लक्ष्य रखा था, लेकिन 10 मार्च से 26 मार्च तक आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण तीन महत्वपूर्ण महीने व्यतीत होने के बाद भी लक्ष्य से थोड़ा कम ही पर काम हो पाया। संसदीय चुनाव के लिए 10 मार्च से 26 मई 2019 तक आचार संहिता लागू होने तथा मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण देश भर में पूर्ण लॉकडाउन के कारण यह समय अनुत्पादक बना रहा।

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गयी मार्जिन मनी (रुपये करोड़ में)	रोज़गार (संख्या)
2016-17	52,912	1281.00	4,07,840
2017-18	48,398	1312.00	3,87,192
2018-19	73,427	2070.00	5,87,416
2019-20	66,653	1951.00	2,57,816

सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियन्स पोर्टल शुरु किया

www.Champions.gov.in

- पोर्टल एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली, आधुनिक आईसीटी टूल सक्षम कंट्रोल रूम का नेटवर्क हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित
- भारतीय एमएसएमई उद्योग को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने का लक्ष्य

बड़ी पहल के तहत सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने चैंपियन्स पोर्टल शुरु किया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने ,गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है।

आधुनिक तकनीक के सांमजस्यपूर्ण अनुप्रयोंगों के साथ छोट उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरुप इस पोर्टल को चैंपियन्स का नाम दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से जुडी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं।

एमएसएमई मंत्रालय के नए सचिव श्री ए के शर्मा ने 30 अप्रैल को पदभार ग्रहण करते समय ही यह संकेत दे दिया था कि वर्तमान कठिन परिस्थितियों में देश के छोटे उद्योगों की मदद करने के लिए एक आईसीटी आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबारी क्षमता बढाने में मदद करेगी। इस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण 9 मई को शुरु किया गया।

यह एक प्रौद्योगिकी पैक नियंत्रण कक्ष-सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसे टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे आईसीटी टूल्स के अलावा, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम बनाया गया है। इसे भारत सरकार की मुख्य केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) और एमएसएमई मंत्रालय की अन्य वेब प्रणालियों के साथ सीधे जोडा गया है। इस पूरी प्रणाली को बिना किसी लागत के एनआईसी की मदद से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इसकी भौतिक अवसंरचना रिकॉर्ड समय में मंत्रालय में ही तैयार की गई है।

सूचना प्रणाली में कंट्रोल रूम का एक नेटवर्क हब एंड स्पोक मॉडल में बनाया गया है। हब नई दिल्ली में एमएसएमई सचिव के कार्यालय में स्थित है और राज्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को इससे जोडा गया है। इस नियंत्रण प्रणाली के हिस्से के रूप में अब तक, 66 राज्यों में स्थानीय स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जा चुके हैं।

इस पोर्टल के लिए एक विस्तृत परिचालन प्रक्रिया जारी की गई है, अधिकारियों की विशेष तौर पर नियुक्ति की गई है और उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। श्री शर्मा ने 9 मई को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चैंपियंस प्रणाली का परीक्षण शुरू किया। इस अवसर पर देश के लगभग 120 स्थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा गया था।

श्री शर्मा ने चैंपियन्स प्रणाली का शुभारंभ करने के अवसर पर कहा कि यह एमएसएमई इकाइयों और उन पर निर्भर लोगों के लिए है। इन इकाइयों और इससे जुडे लोगों को हमारी मदद की बेहद जरुरत है। हम इनकी मदद करने,दोबारा कारोबार शुरु करने तथा पूरी तरह से इनका कायाकल्प करने के लिए सब कुछ करेंगे।

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

Global Prime News
Trusted News Worldwide That Enlightens Your World
The Power Of Journalism at a Click

In the last one year, the turnover of Khadi registered a growth of 31 per cent. **Khadi and Village Industry Commission, KVIC Chairman, Vinai Kumar Saxena** has attributed Khadi's phenomenal growth to the sustained efforts of Prime Minister Narendra Modi.

He said, Prime Minister's repeated appeals from various platforms including his radio address "Mann ki Baat", to adopt Khadi as a necessity of daily life, the KVIC has been continuously going up the growth trajectory.

Mr. Saxena said, in 2018-19, it registered an increase of 31 per cent in the sale of Khadi and over 19 per cent rise in the sale of village industry products despite nationwide lockdown in wake of Covid-19.

The sale of Khadi fabric products increased by 179 per cent from Rs. 1510 crore in 2015 -16 to Rs. 4,211 crore in 2019-20. **ENDS**

Webinar; brings developers associations, channel partners associations, architects engineers associations and allied associations together on a common platform for the first time ever

APN NEWS

Khadi & village industries turnover reaches to Rs. 88, 887 crore in 2019-20

Published on May 8, 2020

The total Khadi and village industries turnover in the year 2019-20, has reached to Rs. 88, 887 crore.

In the last one year, the turnover of Khadi registered a growth of 31 per cent. Khadi and Village Industry Commission, KVIC Chairman, Vinai Kumar Saxena has attributed Khadiis phenomenal growth to the sustained efforts of Prime Minister Narendra Modi.

He said, Prime Minister's repeated appeals from various platforms including his radio address "Mann ki Baat", to adopt Khadi as a necessity of daily life, the KVIC has been continuously going up the growth trajectory.

Mr. Saxena said, in 2018-19, it registered an increase of 31 per cent in the sale of Khadi and over 19 per cent rise in the sale of village industry products despite nationwide lockdown in wake of Covid-19.

The sale of Khadi fabric products increased by 179 per cent from Rs. 1510 crore in 2015 -16 to Rs. 4,211 crore in 2019-20.

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

Social Media Campaigns

• Instagram Grid •

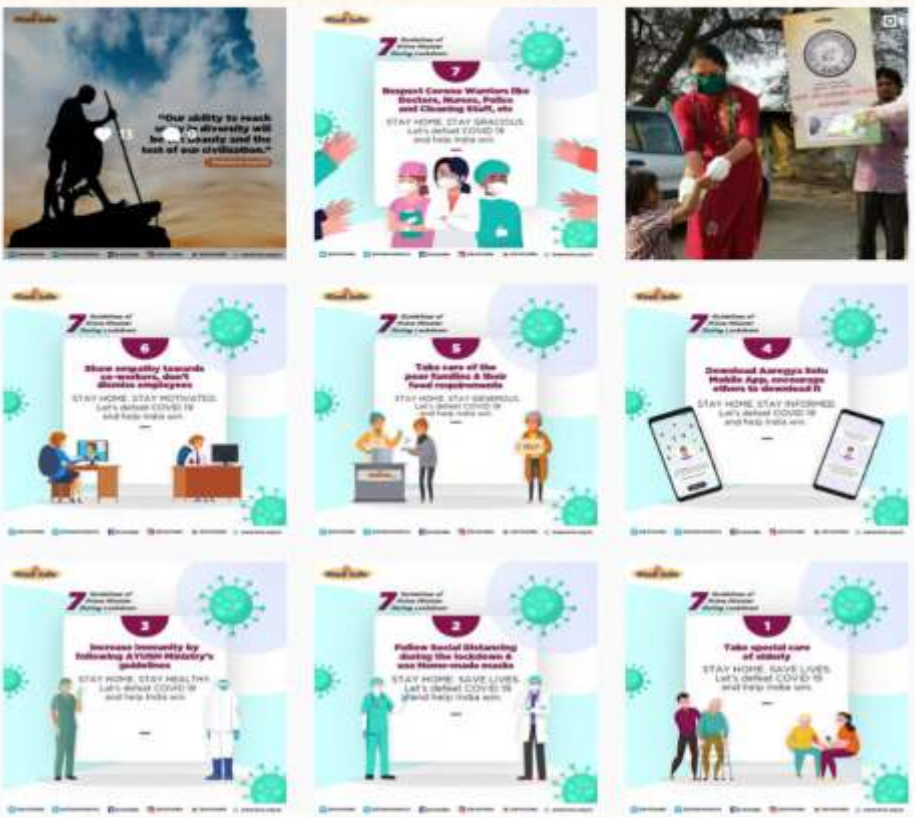

• Special Day posts •

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

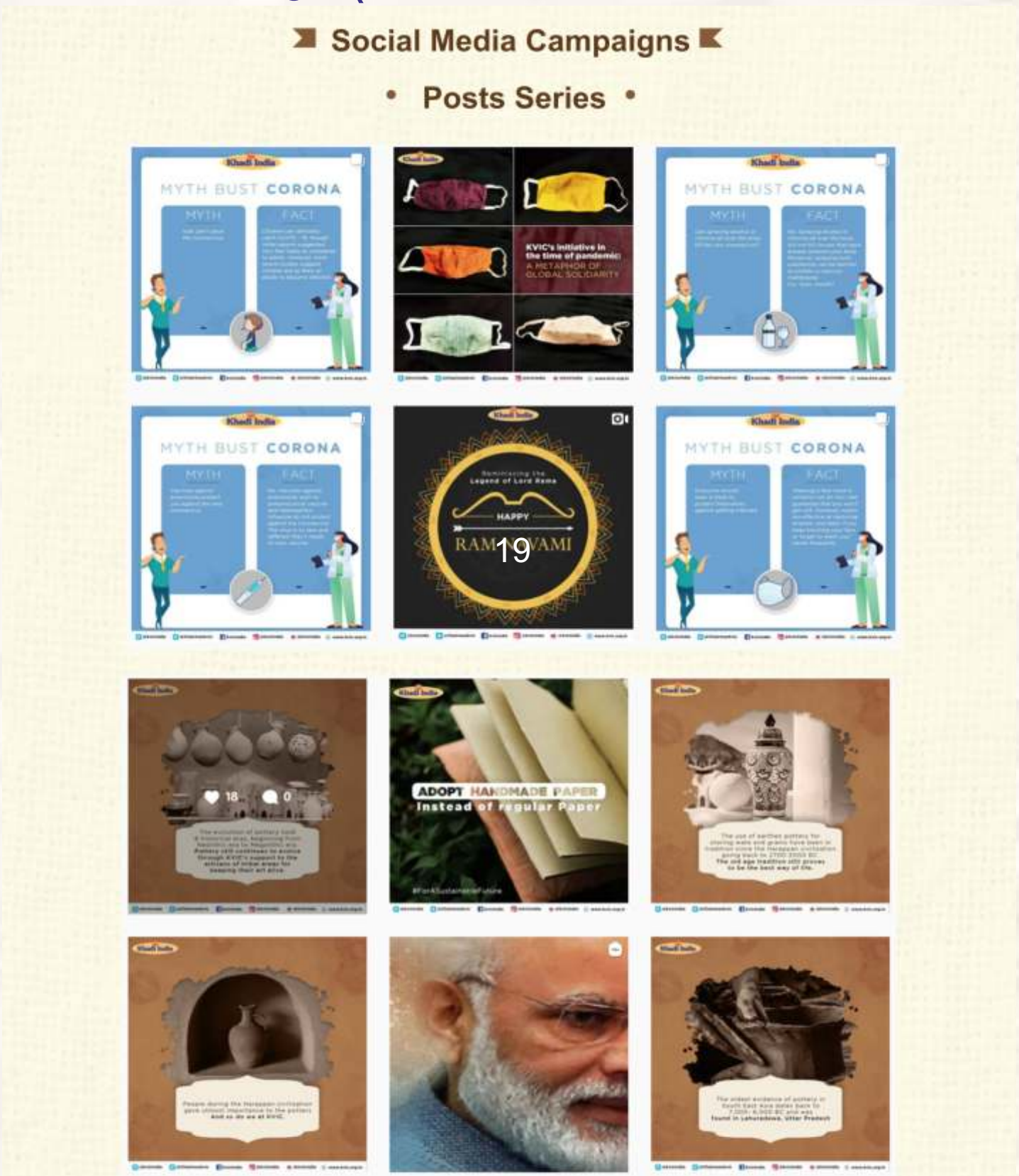

सत्यमेव जयते

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises,
Government of India.

Khadi India

हस्तनिर्मित

स्विट्जरलैंड से पेन और घड़ियाँ,
फ्रांस से चमड़े के जूते,
इटली से पर्स व बटुए और
मिस्र से कॉटन वस्त्र.

आप इन विदेशी वस्तुओं के लिए हजारों खर्च करते हैं और खरीदते हैं,
और जब भारतीय हस्तशिल्प खरीदने की बात आती है, आप संकोच करते हैं !

इस अवसर पर

अपने शहर के किसी खादी इण्डिया आउटलेट पर जाएं,
गर्व से खरीदें उच्च गुणवत्ता के हस्तनिर्मित वस्त्र और उत्पाद,
जो आपके देशवासियों द्वारा ग्रामीण भारत में बनाये गए हैं !

क्यों विदेशी हाथों को भुगतान करें ?
भारत की आत्मीयता को महसूस करें

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
वेबसाइट : www.kvic.org.in

KVIC ARTWING 2018

https://www.msme.gov.in | Follow us on minmsme @minmsme | Website: www.kvic.org.in | Follow us on kvicindia @kvicindia